Curtailment in rail projects due to resource crunch

1784. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether serious resource crunch may force the Railways to cut some of the projects as reported in Statesman of the 6th November, 1995;

(b) if so, the details of the projects likely to suffer due to resource crunch;

(c) whether Railways on its own propose to generate funds for the projects; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH KALMADI): (a) and (b) Railways do not propose to drop any project which have already been sanctioned, in view of the resource crunch.

(c) and (d) For the current year 1995-96, about 55% of the plan size is being financed through internal generation of resources.

Service conditions of Supreme Court and High Court judges

1785. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to improve the service conditions of Supreme Court and High Court judges;

(b) if so, what are the proposals;

(c) whether Government have received suggestions in this regard; and if so, the details thereof; and

(d) by what time a legislation will be brought?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) to (d) Recently, improvements in the service conditions of the Supreme Court and High Court Judges have been made by providing the following liberalised benefits to them:

(1) *For Supreme Court Judges—*

(a) Reimbursement of medical expenses on prescriptions of Government doctors/hospitals or registered medical practioners/ private hospitals by the Registry of Supreme Court of India.

(b) The value of free furnishing at the residence increased from Rs. 1.25 lakhs to Rs. 2.5 lakhs for CJI and from Rs. 1 lakhs to Rs. 2 lakhs for Judges.

(c) Free water and electricity at the residence of Judges w.e.f. 1.4.1994.

(2) *For High Court Judges—*

(a) The value of free furnishing at the residence increased from Rs. 1 lakhs to Rs. 2 lakhs for CJ and from Rs. 70,000/- to Rs. 1.5 lakhs for other Judges.

(b) Additional (third) LTC for the Chief Justice and transferred Judges to visit home State in a year.

(c) Increase in compensatory (transfer) allowance to Rs. 2000/- p.m. or 10% of basic pay, which ever is more, against 10% of the basic pay admissible.

(d) Travel in train by the highest class including air-conditioned while joining office on elevation.

The question of improvement in certain allowances/facilities e.g. sumptuary allowance and conveyance facilities available to the Judges, which require to be made by undertaking amendments to the High Court Judges (C/S) Act, 1954

and the Supreme Court Judges (C/S) Act, 1958, is receiving attention of the Government.

दवाईयों का आयात

1786. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष किन-किन दवाइयों का कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ख) इस समय किन-किन देशों से दवाइयों का आयात किया जा रहा है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयात की गई दवाइयों का मूल्य कितना है;

(घ) प्रत्येक राज्य से प्रति वर्ष किन-किन औषधियों की कितनी-कितनी मात्रा के आयात का अनुरोध किया जाता है;

(ङ) इनमें से किन-किन दवाइयों का देश में उत्पादन नहीं किया जाता है; और

(च) सरकार द्वारा इन दवाइयों के उत्पादन हेतु क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए॰ आर॰ अन्तुले): (क) से (ग) 1994-95 तक देश में औषधों की प्रमात्रा और मूल्यों सहित उनके देश वार किए गए आयात, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित किए गए जो "विदेश व्यापार और भारत" मासिक सांख्यिकी खण्ड-1 के शीर्षक के प्रकाशन में उपलब्ध है। इस प्रयोजन के लिए उक्त प्रकाशन, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, का संदर्भ लिया जा सकता है।

(घ) औषधों के राज्य-वार आयात से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) अयात की गई लेकिन देश में विनिर्मित न की गई औषधों के नामों को दशनि वाला विवरण संलग्न है **(नीचे देखिये)**।

(च) सामान्यतः इन औषधों के उत्पादन का उन्नयन करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में लाइसेंसिंग पद्धति का उदारीकरण, कच्ची सामग्रियों/इंन्टरमीडिएटों के आयात का उदारीकरण, जीवन-रक्षक औषधों के उत्पदान के लिए क्षेत्रीय अधिमानों के हटाना, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण को प्रोत्साहन, स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास के आधार पर औषधों के उत्पादन के लिए कर में राहत और मूल्य नियंत्रण के क्षेत्राधिकार से ऐसे उत्पादन को बाहर निकालना शामिल है।

विवरण

देश में विनिर्मित न की गई आयातित औषधों का विवरण

क्रम सं॰	औषध का नाम
1.	एंटेगोजिल सियोनिमबिन एच॰सी॰एल॰ इंजे॰
2.	अत्रिकुरियम डीसीलेट इन्जे॰
3.	अंटी हेमोफिलिक फैक्टर कोन (VIII एवं IX)
4.	अप्रोटीनिन इंजे॰
5.	अंक्रोटिल टेबलेट (फ्लूशिटोसिन)
6.	एसेप्रोमेरीन मेलिट इंजे॰
7.	बेथानक्रोल क्लोरिड टेबलेट (मयोटोनीन)
8.	बूटलेक्श इंजे॰ (वेट)
9.	कैलशियम ल्यूकोवेरिन इंजे॰
10.	सेट्रेबिन इंजे॰
11.	कटलीन टेबलेट्स
12.	क्लोरेम्बूशिल टेबलेट
13.	क्लोस्टिरम नी ओरल ससपेंशन
14.	कारबोप्लैटिन इंजे॰